शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 17 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 24 – 1 मई 2023 मूल्य पांच रूपए

# वाटर सैस लगाकर संसाधन जुटाने पर लगा प्रश्नचिन्ह

- केन्द्र ने उपकर को असंवैधानिक करार दिया
- गारंटीयां पूरी करने के लिये कर्ज और कर एकमात्र सहारा

**शिमला/शैल।** कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता को दस गारंटीयां दी हैं। इन गारंटीयों को पूरा करने के लिये आर्थिक संसाधन चाहिये। यह संसाधन जुटाने की दिशा में सुक्खू सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सैस लगाने का फैसला लिया। सरकार को अफसरशाही से यह फीडबैक मिला की जल उपकर लगाकर चार हजार करोड़ सरकार को प्रतिवर्ष मिल सकते हैं। यह राय मिलते ही सरकार ने बजट सत्र से पहले ही एक अध्यादेश के माध्यम से यह फैसला लागू कर दिया। बजट सत्र में इस आश्य का विधेयक पारित करके पुख्ता काम कर दिया। बजट सत्र में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से इस पर कई गंभीर सुझाव भी आये थे और उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु और आशंकायें भी उठाई गयी थी। इस उपकर को एक जल विद्युत परियोजना नन्ती जल विद्युत परियोजना प्रा.लि. ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है और उस पर संबद्ध पक्षों को नोटिस भी जारी हो गये हैं।

लेकिन इसी बीच भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से सभी प्रदेशों और केन्द्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम 25 अप्रैल को एक पत्र जारी करके कहा गया है कि ऐसा उपकर लगाना एकदम असंवैधानिक है। पत्र में इस विषय के कानूनी और संवैधानिक पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार का यह फैसला असंवैधानिक और गैरकानूनी है तथा उच्च न्यायालय में टिक नहीं पायेगा। इससे जहां सरकार के संसाधन जुटाने के प्रयासों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है वहीं पर अफसरशाही की गंभीरता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है क्योंकि इस फैसले से जल विद्युत उत्पादन प्रभावित होते हैं और वह इसे अदालत में चुनौती देंगे ही। यहां प्रश्न यह उठ रहा है कि जिन संवैधानिक पक्षों को केन्द्र की अफसरशाही ने उठाया है उन्हें प्रदेश की अफसरशाही नजरअन्दाज कैसे कर गयी। अब केन्द्र के पत्र से इस उपकर पर आपत्ति उठाने वाले उत्पादकों का पक्ष पुख्ता हो जाता है।

इस परिदृश्य में यह स्वभाविक सवाल भी उठेगा कि जब सरकार संसाधन ही नहीं जुटा पायेगी तो फिर यह गारंटियां कैसे पूरी हो पायेंगी। निश्चित है की गारंटिया पूरी करने के लिए सरकार के पास कर्ज लेने और कर लगाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। ऐसे में कर्ज का जो आरोप कल तक पूर्व की जयराम सरकार पर लगता था अब वही आरोप इस सरकार को भी सहना पड़ेगा। क्योंकि केन्द्र के इस पत्र पर राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आयी है। यह पत्र नगर निगम शिमला के चुनावों के मध्य आया है और इसका प्रभाव चुनाव में भी पड़ जाये तो कोई हैरानी नही होगी।

File No. 15/27/2023-Hydel-II (MoP)
Government of India
Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, Dated 25th April, 2023

To

1. Secretary (MNRE), Ministry of New and Renewable Energy, Atal Akshay Urja Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003,
2. CMDs of NTPC Ltd., NHPC Ltd., SJVN Ltd., THDC India Ltd. and NEEPCO
3. The Chairman – BBMB and DVC.

**Subject: Imposition of Water Tax / Cess by various State Government on HEPs – reg.**

Sir,

It has come to the notice of the Government that some States have imposed taxes / duties under various guises on the generation of electricity. This is unconstitutional. The legal and Constitutional provisions have been brought to the notice of the States by the Government of India. A copy of letter to the States is enclosed. The constitutional provisions may be strictly followed. If any unconstitutional taxes / duties are levied by any State in any guise whatsoever; it may be promptly challenged in Court and no payment of such taxes / duties may be made by the Government of India organizations in the business of generating electricity until after a decision by a Competent Court, or legality thereof. As stated in the letter cited, this applies to all forms of generation.

This has the approval of the Hon'ble Union Minister of Power and New & Renewable Energy.

Yours sincerely,.

(R.P. Pradhan)
Director
Email: rp.pradhan@nic.in
Tel.: 011-23717753

File No. 15/27/2023-Hydel-II (MoP)
Government of India
Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, Dated 25th April, 2023

To

The Chief Secretaries – All the State Governments & UTs

**Subject: Imposition of Water Tax / Cess by various State Government on HEPs – reg.**

Sir,

It has come to the notice of the Government of India (GoI) that some State Governments have imposed taxes / duties on generation of electricity. This is illegal and unconstitutional. Any tax / duty on generation of electricity, which encompasses all types of generation viz. Thermal, Hydro, Wind, Solar, Nuclear, etc. is illegal and unconstitutional. The Constitutional provisions are as follows:

(i) The powers to levy taxes / duties are specifically stated in the VII Schedule. List –II of the VII Schedule lists the powers of levying of taxes / duties by the States in entries-45 to 63. No taxes / duties which have not been specifically mentioned in this list can be levied by the State Governments under any guise whatsoever – as Residuary powers are with the Central Government.

(ii) Entry-53 of List-II (State List) authorizes the States to put taxes on consumption or sale of electricity in its jurisdiction. This does not include the power to impose any tax or duty on the generation of electricity. This is because electricity generated within the territory of one State may be consumed in other States and no State has the power to levy taxes / duties on residents of other States.

(iii) Some States have imposed taxes / duties on generation of electricity under the guise of levying a cess on the use of water for generating electricity. However, though the State may call it a water cess, it is actually a tax on the generation of electricity – the tax is to be collected from the consumers of electricity who may happen to be residents in other State.

(iv) Article -286 of the Constitution explicitly prohibits States from imposing any taxes / duties on supply of goods or services or on both where the supply takes place outside the State.

(v) Articles-287 and 288 prohibit the imposition of taxes on consumption or sale of electricity consumed by the Central Government or sold to the Central Government for consumption by the Government or its agencies.

(vi) As per Entry-56 of the Union List of the Constitution of India, regulations of issues related to Inter-State Rivers come under the purview of the Centre. Most of the Hydro-Electric Plants in the States are located / proposed to be developed on Inter-State Rivers. Any imposition of tax on the non-consumptive use of water of these rivers for electricity generation is in violation of provisions of the Constitution of India.

Contd...2.

(vii) Hydro Power Projects do not consume water to produce electricity. Electricity is generated by directing the flow of water through a turbine which generates electricity – on the same principle as electricity from wind projects where wind is utilized to turn the turbine to produce electricity. Therefore, there is no rationale for levy of "water cess" or "air cess".

(viii) The levy of water cess is against the provisions of the Constitution. Entry-17 of List-II, does not authorize the State to levy any tax or duty on water.

2. In light of the above constitutional provisions, no taxes / duties may be levied by any State under any guise on generation of electricity and if any taxes / duties have been so levied, it may be promptly withdrawn.

This has the approval of the Hon'ble Union Minister of Power and New & Renewable Energy.

Yours sincerely,.

(R.P. Pradhan)
Director
Email: rp.pradhan@nic.in
Tel.: 011-23717753

# हमीरपुर चयन आयोग के प्रभावितों का रोष एक बड़े संकट की आहट है

**शिमला/शैल।** हमीरपुर स्थित अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली जे.ओ.ए. (आई.टी) परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना परीक्षा होने से पहले ही पुलिस से लेकर विजिलैन्स तक पहुंच गयी थी। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभाव से कारवाई करते हुये परीक्षा होने से पहले ही कथित दोषियों को पकड़ लिया। यह परीक्षा होने से पहले ही रद्द कर दी गयी। इसके बाद जैसे – जैसे जांच आगे बढ़ी तो सरकार ने बड़ी जांच करवाने के लिये एसआईटी का गठन कर दिया। क्योंकि इससे पूर्व हुई अन्य परीक्षाओं में भी पेपर लीक की आशंकाएं उभरी। इन आशंकाओं के साथ में इस आयोग का कामकाज 26 दिसम्बर को निलंबित कर दिया और आगे चलकर 21 फरवरी को इसे बन्द ही कर दिया। सरकार की कारवाई से दिसम्बर में ही इस आयोग का सामान्य कामकाज रुक गया। परिणाम स्वरूप जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के कगार पर थे वह रुक गये। कुछ परिणाम निकल चुके थे उनमें भी अगली कारवाई रुक गयी। इस तरह हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस आयोग को भंग करने के बाद इसका काम प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। परन्तु अब जब रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर गठित हुई कमेटी की रिपोर्ट सामने आयी और यह पता चला कि विभिन्न सरकारी विभागों में 70,000 पद खाली हैं तब यह भी सामने आया कि पिछले 5 वर्षों में हमीरपुर बोर्ड ने कितनी भतियां की हैं और लोक सेवा आयोग ने कितनी। यह आंकड़ा देखकर यह स्वभाविक सवाल उठा कि ऐसे में तो हमीरपुर बोर्ड के लंबित सौंपे गये काम को तो आयोग को निपटाने में बहुत लंबा समय लगेगा।

यह जानकारी सामने आते ही हमीरपुर बोर्ड के उन अभ्यार्थियों को चिन्ता हो गयी जिन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनका परिणाम मध्य अप्रैल तक घोषित कर दिया जायेगा। यह लोग मुख्यमंत्री से वास्तविक वस्तुस्थिति जानने शिमला उनसे मिलने आ गये। लेकिन मुख्यमंत्री उनसे न ओकओवर में मिले पाये और न ही कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मिल पाये। बल्कि जहां मुख्यमंत्री नगर निगम के लिये चुनावी जनसभा करने गये वहां पर भी नही मिल पाये। इन प्रभावित बच्चों ने जिस तरह से रोष में अपनी व्यथा मीडिया से सांझा की है वह आने वाले दिनों में सरकार के लिये कठिनाइयां पैदा करने वाली हो जायेगी। क्योंकि जो पांच लाख रोजगार उपलब्ध करवाने की गारन्टी दी गयी थी उसमें भी अब पांच साल में एक लाख रोजगार देने की बात आ गयी है। इस तरह सरकार की विश्वसनीयता पर अनचाहे ही प्रश्नचिन्ह लगते जा रहे हैं।

हमीरपुर बोर्ड के प्रकरण में विशेष जांच दल अब तक छः एफ.आई.आर. दर्ज कर चुका है। यह मामले विभिन्न परीक्षाओं को लेकर हुये हैं। इनकी जांच पूरी होने और इनके कथित दोषियों के बाद इस सबसे लाभान्वित हुये लाभार्थियों को चिन्हित करके उन्हें भी आरोपी बनाकर इन मामलों के चालान अदालत में दायर करने तक बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसे में सरकार को हमीरपुर में ही चयन आयोग को फिर से स्थापित करने का प्रयास करना होगा। अन्यथा बच्चों का जो रोष सामने आया है वह आने वाले संकट की आहट है।

# राज्यपाल ने सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर जन सहयोग का आग्रह किया

**शिमला/शैल।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण की राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग की गयी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के माध्यम से इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्यानंद सरैक और नेक राम शर्मा, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों के विजेता और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उल्लेखित प्रदेश के विशिष्ट लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया।

मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण के उपरान्त राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि यह समाज के साथ संवाद का कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। इसके माध्यम से समाज में प्रेरणादायी कार्य करने वाले लोगों को समाज के नायक के रूप में लोकप्रिय करना है। ये नायक लोगों के आदर्श के रूप में स्थापित होकर अन्य के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में जन सरोकार से जुड़े कई विषयों पर संवाद किया गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के लोगों की प्रतिभा का उल्लेख किया है। प्रदेश के प्रतिभाशाली लोग देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं, यह बात प्रशंसा का विषय है। सोलन स्थित मानव भारती संस्था और इससे जुड़ी उर्मिला बाल्दी, संजना और विपुल गोयल, चम्बा के भटियात विधान सभा क्षेत्र के अध्यापक आशीष बैहल, ऊना जिले के गांव भटोली के प्राथमिक अध्यापक राम कुमार जोशी, हमीरपुर के जगदीश चन्द्र और कई अन्य प्रतिभाशाली लोग इस सूची में शामिल हैं।

राज्यपाल ने नशामुक्ति, प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान, प्राकृतिक खेती, पोषणयुद्ध अनाज की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लोगों से इन मुद्दों पर पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आवहान किया। उन्होंने कहा कि यह जन सरोकार के विषय हैं, जिसमें हर व्यक्ति को सहयोग करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर चर्चा सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस उपमहानिरीक्षक (अपराध) डी.के. चौधरी, और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की नशा निवारण विशेषज्ञ डॉ. निधि ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक प्रस्तुति दी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी ने तपेदिक उन्मूलन, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक, रघुबीर सिंह ने पोषणयुक्त अनाज और उप निदेशक, कृषि महेंद्र भवानी ने प्राकृतिक खेती पर एक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर पद्मश्री नेक राम शर्मा ने भी बहुमूल्य विचार व्यक्त किए।

इससे पहले, उप-महानिदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन गुरविंदर सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया। आकाशवाणी की कार्यक्रम प्रमुख पूनम सिंह ने लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ल का स्वागत किया।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के अधिकारी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# विद्यार्थियों के कौशल विकास पर दें विशेष ध्यान: राज्यपाल

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के सीनेट की 16वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिये भी प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि यह हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि यह विश्वविद्यालय देश के आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में पुनर्प्रतिष्ठापित हो। इसके लिए विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं अनुसंधान गतिविधियों को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सीनेट की बैठक को नियमित तौर पर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष अपनी घरेलू आय 30.74 करोड़ रुपये अर्जित की है तथा विश्वविद्यालय केंद्र सरकार से भी अनुसन्धान व शिक्षा कार्यों के लिए भारतीय षि अनुसन्धान परिषद से अनुदान ले रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्य परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए और प्रयास किये जाने चाहिये।

शुक्ल ने कहा कि इस अवधि में विश्वविद्यालय ने बुनियादी ढांचा विकसित करने में काफी प्रगति की है। इस दिशा में पिछली सीनेट की बैठक से अब तक 37.99 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों पर खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आधुनिक प्रयोगशालाएं, छात्रों के लिए अध्ययन-कक्ष, ई-काट्र्स तथा सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट व छात्रों के लिए एक सोलर स्टीम किचन जैसी सुविधाएं स्थापित की गयी हैं।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान 4 हजार 623 नई किताबें, पत्रिकाएं और थीसिस पुस्तकालय संग्रह में जोड़ी गयी हैं। उन्होंने कहा कि समाज की नई पीढ़ी को मात्र उपाधिधारक बना देने से हमारा दायित्व पूरा नहीं हो सकता। अपितु युवाओं में सम-सामयिक चुनौतियों का सामना करने का साहस और क्षमता विकसित करना भी हमारी जिम्मेदारी है तभी विश्वविद्यालय सही मायनों में अपनी भूमिका को निभा पाएगा।

विधायक एवं विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य विनोद सुलतानपुरी तथा अजय सोलंकी ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चन्देल ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान भौतिक विकास के साथ-साथ अकादमिक उपलब्धियां विश्वविद्यालय ने अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों के माध्यम से 89 परियोजनाएं अनुसंधान के लिये पिछले पांच वर्षों में मिली हैं और पिछले माह में नाबार्ड ने इस के लिये 29 लाख रुपये का अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक कृषि के लिये विश्वविद्यालय को अभी तक 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में विश्वविद्यालय ने करीब 31 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है।

निदेशक अनुसंधान, डॉ. संजीव चौहान ने शोध गतिविधियों तथा विस्तार शिक्षा, डॉ. इंदर देव ने विस्तार गतिविधियों पर अपनी प्रस्तुति दी।

रजिस्ट्रार संदीप नेगी ने बैठक की कार्यवाई का संचालन किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा

# देवभूमि की पवित्रता को बनाये रखने के लिए नशे से दूर रहें युवा: राज्यपाल

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं का आहवान किया कि देवभूमि हिमाचल की पवित्रता को बनाये रखने के लिए नशे से दूर रहें और प्रतिज्ञा लें कि नशा नहीं करेंगे।

राज्यपाल सोलन जिले के नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में छात्रों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व, उन्होंने 75 लाख रुपये की लागत से पहाड़ी शैली में निर्मित विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेशद्वार का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की अंतर कालेज खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ भी किया।

हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने इस संस्थान से जुड़े लोगों से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सेब राज्य के रूप में देश-विदेश में पहचान है।

शिक्षा, शोध व प्रसार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बागवानी व सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास में इस विश्वविद्यालय ने सक्रिय भूमिका निभाई है और अपनी स्थापना की प्रासंगिकता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को सेब राज्य के रूप में पहचान दिलाने में भी विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शैक्षणिक संस्थानों की अटल रैंकिंग के तहत वर्ष 2021 में इस विश्वविद्यालय को प्रोमिसिंग बैंड में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी देश के 72 कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिग में इस विश्वविद्यालय को 22वां स्थान प्रदान किया। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल ग्रीन यूनिर्वसिटी अवार्ड-2022 से नवाजा गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

शुक्ल ने कहा कि शिक्षण कार्य के साथ-साथ यहां खेलकूद व अन्य गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं और यहां अध्ययनरत लोकेश भनोट और संध्या जैसे छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित 99.41 करोड़ रुपये की 89 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें से 2022-23 में 9.92 करोड़ रुपये की 28 परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय को अनुसंधान, नवोन्मेष और तकनीक के माध्यम से किसानों को अच्छी और कम लागत की तकनीक उपलब्ध करवाने पर बल दिया। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर वैज्ञानिकों से अपील की कि वे बागवानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित करें।

# मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 में जुड़ेगी वाट्सएप चैटबॉट सुविधा:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 को अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए सरकार इसमें नई सुविधाएं जोड़कर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे नागरिकों को उनकी शिकायतों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने, प्रतिक्रिया प्रदान करने, कॉलबैक का अनुरोध करने और नई शिकायतें दर्ज करने की और बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

शिकायत संबंधी सुविधाओं के अलावा, व्हाट्सएप चैटबॉट विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी भी प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों की शिकायतों के त्वरित निपटारे व और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने कामकाज में वृहद स्तर पर प्रौद्योगिकी को शामिल करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैटबॉट का विकास पहले ही शुरू किया जा चुका है, और इस नई सुविधा से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 की दक्षता और पहुंच में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करना और अपनी शिकायतों का समाधान और आसान हो जाएगा।

राज्य सरकार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों की हेल्पलाइन सेवाओं को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से जोड़ने की दिशा में भी कार्य कर रही है। यह कदम नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा और उनके मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, हेल्पलाइन का उपयोग बेसहारा मवेशियों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। इसके लिए आग्रटी विभाग ने एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की है। इससे उपयोगकर्ता बेसहारा मवेशियों की तस्वीरें लेने और उनके स्थान इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसमें प्राप्त जानकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी, जो इसका उपयोग इन पशुओं को चिन्हित करने और उचित कारवाई के लिए कर सकते हैं। इस एप्लिकेशन में जीपीएस ट्रैलकग, जियो-टैलगग और पुश नोटिफिकेशन जैसी विशेषताएं शामिल होंगी। इससे अधिकारी के स्तर पर शीघ्र कारवाई भी सुनिश्चित हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में सुधार और महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। प्रौद्योगिकी से विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के एकीकरण और बेसहारा पशुओं की निगरानी सुनिश्चित कर सरकार समस्या-समाधान और जन सेवा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है।

# न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'न्याय एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालीन न्यायिक विकास एवं सुदृढ़ीकरण' (कंटेम्परेरी ज्यूडिशियल डिवलेपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस थ्रू लॉ एंड टैक्नोलॉजी) विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्र-दो के क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता, उत्पादिता और दक्षता सुनिश्चित कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से न्यायपालिका सहित आज हर क्षेत्र में आम लोगों के जीवन को सरल बनाने में मदद मिली है।

उन्होंने न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को एक सहायक के रूप में रेखांकित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में गति आयी है। कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई सभी के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे लोगों के धन और समय दोनों की बचत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सजग और आत्मविश्वासी समाज के साथ-साथ देश के विकास के लिए एक विश्वसनीय और त्वरित न्यायिक प्रणाली आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब न्याय मिलता नज़र आता है, तो संवैधानिक संस्थाओं में आम आदमी का विश्वास और भी बढ़ जाता है तथा कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और इसमें निरंतर सुधार भी संभव हो पाता है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न्याय में देरी देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और न्यायपालिका इसके समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण विभिन्न विवादों को सुलझाने का एक साधन है और इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के लिए तकनीक के अनुरूप कानूनी शिक्षा तैयार करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन नए विचारों की व्युत्पत्ति और देश में कानूनी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में दूरगामी सिद्ध होगा जिससे देश के लोगों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान 'हम, भारत के लोग' के रूप में सभी को एकता के सूत्र में पिरोता है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य हमारे लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता है। संविधान हमारे लोकतंत्र का आधार है, और यह तीन स्तंभों पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि इन स्तंभों को अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में काम करना चाहिए जिससे कि पारदर्शिता, सामाजिक समृद्धि तथा आपसी सामंजस्य और प्रगाढ़ हो सकेगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह स्वयं विधि विषय के विद्यार्थी रहे हैं और इसमें उनकी गहरी रुचि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को चार न्यायाधीश दिए हैं जो प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है।

इससे पहले, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि न्यायपालिका राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते संविधान को आकार देने और इसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन न्यायालयों में कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), क्रिप्टो-मुद्रा, सूचना और संचार सहित अन्य प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक न्यायमूर्ति एपी साही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।

# पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए सरकार के सशक्त प्रयास

**शिमला/शैल।** जल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर के मुख्य निर्धारक हैं। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक और इनके दीर्घकालिक लाभकारी प्रभाव होते हैं।

हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पांच शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में स्वच्छता सेवाओं में सुधार लाने के लिए फ्रेंच डवेलेपमेंट एजेंसी, फैकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) के साथ 817.12 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इसके माध्यम से इन शहरों में पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता में और सुधार लाया जाएगा।

इस परियोजना के तहत एएफडी द्वारा 612 करोड़ रुपये जबकि प्रदेश सरकार द्वारा 204.85 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन पांच शहरों में परियोजना के लाभार्थियों को घरेलू सुविधा कनैक्शन दिए जाएंगे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए जाएंगे ताकि कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जा सके।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों में सुधार, जल जनित रोगों को कम करना, स्थानीय नियमों व अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सुविधाओं का संचालन करना और पेयजल एवं स्वच्छता को किफायती बनाना है।

इसके प्रथम चरण में कुल 485.85 करोड़ रुपये से एएफडी द्वारा 340 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में परियोजना की कुल लागत 371 करोड़ रुपये में से एएफडी 272 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस परियोजना को आगामी तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा और इसका द्वितीय चरण पहले चरण के 18 महीने के बाद शुरू हो जाएगा।

# राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कालाअंब में तीन फर्मों का निरीक्षण किया

**शिमला/शैल।** आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा सिरमौर जिले के काला अंब क्षेत्र में तीन फर्मों का निरीक्षण किया जा रहा है। ये तीनों कंपनियां पांच राज्यों में फैली लगभग 300 फर्मों के नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन 300 फर्मों ने 8300 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन कर 1500 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। इस नेटवर्क की फर्मों की नकद भुगतान के माध्यम से कर देनदारी लगभग नगण्य है और फर्मों ने बताया है कि उनके द्वारा की गई अधिकांश देनदारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से अदा कर दी गयी है।

उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग की आर्थिक खुफिया इकाई (ईआईयू) ने विभिन्न डेटा स्रोतों के माध्यम से डेटा की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन 300 संस्थाओं के बीच लेन-देन में काफी जटिलताएं हैं और इन्होंने नकली/अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ही यह जाल बुना था।

यूनुस ने बताया कि इस पैटर्न से यह भी सामने आया कि ये नई पंजीकृत इकाइयां बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में लेन-देन की घोषणा कर रही थी और खुद ही रद्द करवा रही थी। आपूर्ति श्रृंखला की शुरुआत में संस्थाओं ने कभी भी सरकार को कर का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला की शुरुआत में बड़ी संख्या में संस्थाओं को कर अधिकारियों द्वारा पूर्वप्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया है जिससे पता लगता है कि इन फर्मों ने कागजों में जाली लेन-देन घोषित किया है। उन्होंने बताया कि इन फर्मों के कुछ भागीदार पहले भी कर चोरी की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे।

उन्होंने बताया कि काला अंब में तीन अलग-अलग स्थानों पर तीन जिलों के 24 अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी इकाई के सहयोग से दो संस्थाओं ने अन्य करदाताओं को 250 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ पहुंचाया। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क के विरुद्ध जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार कारवाई की जाएगी।

# चिकित्सा पर्यटन के लिए हिमाचल एक आदर्श गंतव्य:डॉ.शांडिल

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने नई दिल्ली में आयोजित एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के छठे संस्करण के अंतर्गत संवाद सत्र में भाग लिया। इस सत्र में विभिन्न मंत्रालयों, औद्योगिक क्षेत्र और स्टार्टअप्स से जुड़े विशेषज्ञ एवं हितधारक शामिल हुए।

भारत समूह-20 (जी-20) की अध्यक्षता कर रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ मिलकर 'वन अर्थ वन हेल्थ, एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023' के इस छठे संस्करण का आयोजन कर रहा है।

आयोजन के दौरान मेडिकल वैल्यू ट्रैवल अवार्ड्स-2023 को संबोधित करते हुए डॉ. शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अपार सौंदर्य से नवाजा है और यहां का शांत एवं स्वच्छ वातावरण भारत में चिकित्सा सेवाओं के लिए आने वाले विभिन्न रोगियों के लिए एक उपयुक्त गंतव्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, खान-पान, सुंदर वादियां, खूबसूरत पर्यटन स्थल, मंदिर, गोम्पा व मठ बड़ी संख्या में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिलने से यहां के लोगों के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने स्वास्थ्य एवं देखभाल को बढ़ावा देने के दृष्टिगत इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि पर्यटन को स्वास्थ्य से जोड़ने की यह पहल न केवल चिकित्सा कारणों से यहां आने वाले यात्रियों को लाभ प्रदान करेगी, अपितु विभिन्न राज्यों की आर्थिकी को भी गति देगी।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के अवसर पैदा करने पर बल देना है। यह प्रतिभागियों को दुनिया भर में सहयोगियों के साथ नेटवर्क बनाने, विचारों का आदान-प्रदान करने, संपर्क बढ़ाने और मजबूत व्यावसायिक साझेदारी में सक्षम बनाएगा।

इस सम्मेलन में 125 प्रदर्शक और 70 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन, विदेश, वाणिज्य और उद्योग तथा आयुष मंत्रालय, उद्योग मंचों, स्टार्टअप आदि के प्रमुख वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ संवाद एवं चर्चा भी की गयी।

# प्रदेश सरकार ने अनुबन्ध तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कीं

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक दो वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबन्ध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, 30 सितंबर, 2023 को दो वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को भी इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक चार वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। इसी प्रकार 30 सितंबर, 2023 को चार वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगियों की सेवाओं को इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन निर्णयों से संबंधित अधिसूचना जारी की गयी है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्य की विकट वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता पहले ही जारी किया जा चुका है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर कर्मचारियों की लम्बित मांग को भी पूरा किया है। इस निर्णय से 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। यह निर्णय राज्य के विकास में अहम योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय ले रही है।

शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए।

..... आचार्य चाणक्य

## सम्पादकीय

# क्या हिमाचल कांग्रेस राहुल के साथ हैं

राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में उन्हें दो वर्ष की सजा सुना दी। इस फैसले का तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुये लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी और उसके बाद उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी थमा दिया। राहुल ने इस आदेश की अनुपालना करते हुये आवास खाली कर दिया। सूरत की जिस अदालत ने सजा दी थी उसी ने उन्हें अपील के लिए तीस दिन का समय देते हुये अपने फैसले पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन लोकसभा सचिवालय ने इस समय तक इन्तजार करने की बजाये तुरन्त कारवाई कर दी। लोकसभा सचिवालय की इस कारवाई पर पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रियाएं उभरी हैं और यह एक बड़ी राष्ट्र बहस का विषय बन गया है। हर राजनीतिक दल और नेता को इस पर अपना स्टैंड लेना पड़ा है। कोई भी तटस्था की स्थिति में नही रह पाया है। कानूनी लड़ाई के साथ-साथ इसका राजनीतिक पक्ष बहुत बड़ा बन गया है। क्योंकि यह सजा किसी हत्या, अपहरण, डकैती या भ्रष्टाचार के मामले में नहीं वरन चुनावी सभा में दिये गये एक ब्यान पर हुई है। बल्कि इस सजा और उस पर हुई कारवाई से देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य को लेकर उठे सवाल अपरोक्ष में और पुख्ता हो जाते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ हुई कारवाई के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल और युवा सेवाएं मंत्री हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा 2019 में शाहीन बाग में दिये भाषण देश के गद्दारों को गोली..... का प्रकरण भी सीपीएम नेता वृंदा करात ने सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संबद्ध पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिये हैं। राहुल और अनुराग के ब्यानों की यदि तुलना की जाये तो अनुराग का ब्यान ज्यादा गंभीर है। अनुराग हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इस नाते हिमाचल में अनुराग के ब्यान पर राहुल गांधी के परिपेक्ष में प्रदेश में ज्यादा सवाल उठने चाहिये थे। इन सवालों से प्रदेश की जनता राहुल द्वारा लोकतंत्र पर उठाये प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि न मीडिया ने और न ही प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने इस पर मुंह खोला। यही नहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आनन्द शर्मा इस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है परन्तु उनके पास सरकारी आवास है और उसे खाली करवाने के लिये मोदी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। यही स्थिति गुलाम नबी आजाद, मायावती, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की है। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रश्न उछल चुके हैं। परन्तु हिमाचल में कोई कांग्रेस नेता इस पर जुबान खोलने का साहस कर रहा है जबकि यहां कांग्रेस की सरकार है। आनन्द शर्मा की सांसद निधि से नादौन आदि क्षेत्रों में बहुत काम हुये हैं। आनन्द शर्मा के बड़े स्तर पर प्रदेश में समर्थक हैं।

अनुराग और आनंद शर्मा का प्रसंग उठना इसलिये प्रसांगिक है कि यह दोनों नेता हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। यदि प्रदेश में इन पर सवाल उठेंगे तो यह जवाब देने के लिये उपलब्ध होंगे। इस समय राहुल के खिलाफ हो रही कारवाई को भाजपा और उसके मित्र जायज ठहरा रहे हैं। ऐसे में यदि तथ्यों पर आधारित कांग्रेस शासित राज्यों में भी सवाल नहीं उठाये जाएंगे तो जनता राहुल के समर्थन में कैसे आगे आ पायेगी। जिन बुनियादी सवालों पर राहुल आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं यदि उन पर कांग्रेस शासित राज्यों में ही जन आन्दोलन न खड़ा हो पाये तो यह लड़ाई कैसे जीती जायेगी। आज यदि कांग्रेस नेतृत्व कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों की कार्यशैली पर ही नजर नहीं रख पायेगा तो 2024 की लड़ाई जितना कठिन हो जायेगा। जो आरोप भाजपा सरकारों पर लगते आये हैं यदि कांग्रेस की सरकारें भी उन्हीं आरोपों से घिर जायेगी तो जनता क्यों कांग्रेस पर विश्वास करेंगी।

# स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से बन रहे 'गरीबों के आशियाने'

## योजना के तहत मंडी जिले में 4293 मकान बनाने को दी गई 63.11 करोड़ की सरकारी मदद

**शिमला।** हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का मकान हो, एक ऐसा खुशियों का घरौंदा जहां पूरा परिवार हंसी खुशी साथ साथ रह सके, एक साथ जिंदगी गुजार सके। लेकिन कईयों के ये सपने गरीबी के कारण, आर्थिक वजहों से पूरे नहीं हो पाते। अपने पक्के मकान के लिए उन्हें सहारे की, मदद की दरकार रहती है।

ऐसे लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार बड़ा आसरा बनी है। सरकार प्रदेश के लोगों को अपना पक्का मकान बनाने में भरपूर मदद कर रही है। इस मकसद से सरकार ने अपनी विभिन्न आवास योजनाओं के जरिए हर तबके के पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए आर्थिक मदद देने के प्रावधान किए हैं। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने के लिए 'स्वर्ण जयंती आश्रय योजना' में मदद दी जा रही है।

मंडी के जिला कल्याण अधिकारी किरण कुमार बताते हैं कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के जरिए मंडी जिले में वर्ष 2018-19 से अब तक 4293 मकान बनाने के लिए 63.11 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी मदद प्रदान की गयी है।

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में पक्का मकान बनाने को सरकार से मिली 1.50-1.50 लाख रुपये की मदद के लिए मंडी जिले के हजारों लाभार्थी सरकार का आभार जताते नहीं थकते। उनका कहना है कि सरकार ने उनके सपने पूरे किए हैं, इसके लिए जितना धन्यवाद करें कम है।

सदर उपमंडल के छनबाड़ी गांव की कांता देवी ने बताया कि उनके कच्चे मकान में बरसात में पानी आता था, उनका परिवार बहुत खुश हैं कि सरकारी मदद से अब उनका पक्का मकान बन सका है। कांता के पति राजेंद्र कुमार ने भी मकान बनाने के लिए सहायता राशि देने के लिए सरकार का आभार जताया है।

वहीं सरकार की सहायता से गृह निर्माण करने वाले पधर उपमंडल के गांव बसेहड़ की पूर्णिमा, गोहर उपमंडल के गांव वाहवा के लाभार्थी डोले राम और कुंती देवी तथा गांव कुटाहची के पता राम तथा करसोग उपमंडल के गांव विहाल के खेम राज तथा करसोग की प्रेमी देवी ने बताया कि बारिश में घर की कच्ची छत टपकती थी अब पक्का घर बनाने को मिली सरकार की मदद से उनकी चिंता दूर हो गयी है।

करसोग के ग्राम पंचायत ममेल के प्रधान नारायण सिंह ठाकुर ने बताया कि उनके गांव में 14 गरीब लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए धनराशि सरकार ने स्वीकृत की है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते है।

हिमाचल सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पात्र व्यक्ति के नाम जमीन होना जरूरी है। प्रदेश सरकार ने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में गृह निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है। पक्का मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पात्र व्यक्ति के नाम जमीन होना जरूरी है। प्रदेश सरकार ने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में गृह निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है।

उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी का कहना है कि मंडी जिले में सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे समर्पण से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में 4 हजार से ज्यादा पात्र लोग कवर किए गए हैं।

# बच्चों के स्वस्थ जीवन का आधार टीकाकरण

**शिमला।** विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल, 2023 तक दुनियाभर में मनाया गया। इस वर्ष इस सप्ताह का विषय 'दि बिग कैच-अप' रहा। हिमाचल प्रदेश में भी इस सप्ताह को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य प्रत्येक पात्र शिशु तथा गर्भवती महिला को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा टीकाकरण से छूटे हुए लाभार्थियों को कवर करना था।

हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण शिविर लगाए गए तथा जागरूकता गतिविधियां भी संचालित की गईं ताकि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण की महत्ता से अवगत करवाया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत झुग्गियों, प्रवासी आबादी वाले क्षेत्र, श्रमिक शिविरों तथा स्थायी बस्तियों जैसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में टीकाकरण पर बल दिया गया।

प्रदेश में विभिन्न टीकाकरण सत्रों के दौरान लगभग 600 बच्चों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में प्रतिवर्ष 390 स्थानों पर 44 हजार टीकाकरण सत्रों के माध्यम से लगभग एक लाख शिशुओं तथा 1.20 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान खसरा (मिज़ल) तथा रूबेला को समाप्त करने पर बल दिया गया।

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी ने जानकारी देते हुए कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती माता, शिशु के जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को 11 बीमारियों के बचाव के लिए निःशुल्क टीके लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में नियमित टीकाकरण, फ्रेक्शनल आईपीवी की तीसरी डोज के बारे में

विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।

नियमित टीकाकरण के साथ 9 माह के बच्चों को फ्रेक्शनल आईपीवी की तीसरी डोज भी दी गई जो बच्चों को नौवें महीने में मिज़ल-रूबेला (एम. आर.) के टीके साथ दी जाती है। यह बच्चे की बाईं बाजू के ऊपरी भाग में लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि कौन-सा टीका कहां पर और किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है। टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों को समाप्त करते हुए बताया कि टीकाकरण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इससे बच्चे बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं।

टीकाकरण बिल्कुल सुरक्षित है तथा बच्चों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत होती है। यह सभी टीके सभी बच्चों को निःशुल्क सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। जन्म के समय बच्चों को हेपेटाइटिस बी, पोलियो, बीसीजी की खुराक जरूर दिलवानी चाहिए। अगर बीसीजी न लगा हो तो 6 सप्ताह में टीकाकरण की खुराक के साथ जरूर लगवानी चाहिए। एक वर्ष तक बीसीजी का टीका, रोटा वायरस की पांच बूंदें, 6वें, 10वें तथा 14वें सप्ताह में ज़रूर पिलानी चाहिए। लोगों को टीकाकरण की बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है।

# भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत ने दुनिया भर के जी20 के प्रतिनिधियों पर अमिट छाप छोड़ी है: अनुराग सिंह ठाकुर

**शिमला।** वाई 20 प्री-समिट लेह में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्री-समिट 26 से 28 अप्रैल के दौरान आयोजित की गयी थी।

इस समिट की समाप्ति के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में जी20 ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा और विचार-विमर्श सफलतापूर्वक चल रहे हैं और साथ ही भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि लेह में वाई20 प्री-समिट में भाग लेने वाले लगभग 103 प्रतिनिधि लेह के मठों, संगम और मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से मंत्रमुग्ध हैं और वे फिर से लद्दाख लौटना चाहते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों द्वारा लेह में प्री-समिट का आयोजन नहीं किए जाने संबंधी ब्यानों और इसके बारे में भ्रम पैदा किए जाने के बावजूद वाई 20 प्री-समिट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है।

उन्होंने यह भी बताया कि लेह में आयोजित प्री-समिट के परिणामस्वरूप भाग लेने वाले देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच वाई 20 समिट के पांच विषयों पर सहमति बनी है। उन्होंने यह भी बताया कि कौशल से दुबारा लैस करने (रीस्किलिंग) और कौशल को उन्नत करने (अपस्किलिंग) सहित भविष्य की चुनौतियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं।

यह बैठक साझा भविष्य वाले वाई 20 के पांच विषयों पर केन्द्रित थी: लोकतंत्र और शासन में युवा, काम का भविष्य: उद्योग 4.0, नवाचार एवं 21वीं सदी के कौशल, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी: स्थिरता को जीवन जीने का एक तरीका बनाना, शांति निर्माण और सुलह: युद्धरहित युग की शुरुआत तथा स्वास्थ्य, आरोग्य एवं खेल: युवाओं के लिए एजेंडा ।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधियों के साथ युवा संवाद आयोजित किया। उन्होंने कहा कि आकांक्षाओं की विमान पट्टी युवाओं के सपनों की उड़ान भरने हेतु तैयार है। चाहे वह अर्थव्यवस्था के लिए हो या शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के बारे में हो या फिर उद्यमिता के लिए, कौशल विकास से संबंधित हो अथवा डिजिटलीकरण के लिए हो। देश के युवा-अब वैश्विक प्रभाव बनाने के उद्देश्य से एक मिशन मोड पर आ चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वाई20 शिखर सम्मेलन युवाओं और विश्व को समान रूप से अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद को आकार देने का एक असाधारण अवसर प्रदान

कर रहा है। यह कई मायनों में हमारे संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान खोजने में लगातार प्रयासरत है।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह एक ऐतिहासिक समय है, जब आशापूर्ण दृष्टि और अवसर एक साथ आ रहे हैं। यूथ 20 जैसे मंचों पर आने वाले कल के मैत्रीपूर्ण गठबंधन आकार ले रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से नए विचारों की तलाश करने, नवीन संबंधों को विकसित करने और परिवर्तन को लाने के लिए भी आ}वान किया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन ही एकमाञ अपरिवर्तनशील है और इसलिए आप समय से आगे रहते हैं, परिवर्तन की आशा करते हैं तथा इसे गतिमान रखते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हम मानव इतिहास के सबसे महानतम युग में रह रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको एक ऐसी दुनिया विरासत में प्राप्त हुञ्र है, जो आपके लिए पहले से कहह्न अधिक सुख-सुविधाओं, अवसरों, संरचनाओं, प्रणालियों एवं व्यवस्थाओं से सुसज्जित है, ताकि आप अपने और अपने परिवेश के लिए कुछ तैयार कर सकें।

उन्होंने इस संदर्भ में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी पिछली सदी की प्रगति को मील के पत्थर की तुलना में बहुत छोटा बना देगी, जिसे यह नई (युवा) पीढ़ी खोजेगी।

उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझना चाहिए कि आप सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि - सपने देखें, पढ़ें, लिखें, सोचें और निडर होकर कार्य करें!

उन्होंने यह भी कहा कि वाई 20 की थीम को युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सावधानी से चुना गया है, ताकि वे जी20 के विकास एजेंडे और समग्र रूप से वैश्विक समुदाय का निर्माण कर सकें, इसमें सहयोग दे सकें और इसके लिए योगदान कर सकें।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस दशक के अंत तक, विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स महत्वपूर्ण रूप से विकसित हो जायेंगी और हमारे जीवन पर डेटा विज्ञान का प्रभाव और व्यापक हो जाएगा।

युवाओं को इन कौशल के साथ तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने आग्रह किया कि युवाओं को अतीत की सीमाओं से आगे जाना चाहिए, वर्तमान के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और भविष्य में अपने देशों की क्षमता को सामने लाना चाहिए!

उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें पूर्वाग्रहों, पूर्व-कल्पित धारणाओं और अतीत के दो ध्रुवों वाले विश्व दृष्टिकोण में उलझना नहीं चाहिए।

युवा संवाद में अनुराग सिंह ठाकुर ने भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और युवाओं, स्टार्ट अप, महिलाओं, कौशल विकास, शिक्षा आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समापन समारोह में भाग लिया, जहां आजादी की अमृत कहानियां पर दो लघु वीडियो लॉन्च किए गए। इस अवसर पर मोदी/20 पुस्तक का विमोचन भी किया गया। ल न्च कार्यक्रम में लेह-लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में ताशी ग्यालसन, मुख्य कार्यकारी पार्षद और जामयांग सेरिंग नामग्याल, सांसद, लद्दाख भी उपस्थित थे।

# पर्यटन उद्योग में स्टार्ट-अप और उद्योग समूहों के संगठनों के लिए निवेश के अपार अवसर: जी. किशन रेड्डी

**शिमला।** भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 26 और 27 अप्रैल को नई दिल्ली तथा मुंबई में रोड शो का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आगामी प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन के बारे में यात्रा और पर्यटन उद्योग के हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना था। पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रोड शो की अध्यक्षता की।

रोड शो में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, जी. किशन रेड्डी ने कहा, 'भारतीय पर्यटन उद्योग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों वेलनेस, एंडवेचर टूरिज्म, इको-टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, आध्यात्मिक पर्यटन के विभिन्न अनुभवों को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें पर्यटन के उस महत्व को पहचानती हैं जो आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए विशेष रूप से होटल और पर्यटन से संबंधित मूलभूत ढांचे के विकास के लिए निजी निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दिल्ली के इस कार्यक्रम में सरोवर होटल्स के प्रबंध निदेशक अजय बकाया, लेमन ट्री होटल्स के चेयरमैन और एमडी पाटु केसवानी, सीआईआई नेशनल कमेटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के सह-अध्यक्ष मेक-माई-ट्रिप के संस्थापक और अध्यक्ष दीप कालरा तथा आईटीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक नकुल आनंद सहित उद्योग क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित हितधारक शामिल थे। उन्होंने इस क्षेत्र के अवलोकन और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किये।

27 अप्रैल को आयोजित मुंबई रोड शो में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में सौरभ विजय, प्रधान सचिव (पर्यटन), महाराष्ट्र सरकार, हरित शुक्ला, सचिव (पर्यटन), गुजरात सरकार, विवेक श्रोत्रिय, अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश शामिल थे। राजस्थान सरकार के पर्यटन बोर्ड के संयुक्त निदेशक पवन जैन ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए।

भारतीय उद्योग परिसंघ डब्ल्यूआर (पर्यटन और आतिथ्य) की उपसमिति के सह-अध्यक्ष और कामत होटल्स इंडिया लिमिटेड के मुख्यकार्यकारी अधिकारी विशाल कामत, द लीला पैलेस, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग भटनागर, क्रूज एंड नेवी सेल के प्रमुख और जेएम बक्सी एंड कंपनी के उपाध्यक्ष कमांडर नेविल मलाओ, विशिष्ट सेवा मेडल

(वीएसएम) (सेवानिवृत्त), इमेजिका के सीईओ श्री धीमंत बख्शी, होटल, महिंद्रा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के मुख्यकार्यकारी अधिकारी संतोष कुटी शामिल थे। मुंबई में रोड शो में इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ अपने विचार साझा किये।

व्यावसायिक संगोष्ठी के दौरान, जी. किशन रड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, सरकार मिशन मोड में भारत में पर्यटन के विकास और उन्नयन के लिए निरंतर समर्पित रूप से काम कर रही है। घरेलू और विदेशी पर्यटकों को अविस्मणीय अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं।

आगामी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन निवेशक सम्मेलन (ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट) का उद्देश्य भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है और निवेशकों के साथ-साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों को निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। भाग लेने वाले राज्यों को पर्यटन के बुनियादी ढांचे के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों में निवेश योग्य तैयार परियोजनाओं के संदर्भ में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। शिखर सम्मेलन से भारत के पर्यटन उद्योग के तीव्र विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच सार्थक चर्चा और सहयोग की आशा है।

प्रथम ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट (जीटीआईएस) 2023 का संवर्धन और सुविधा भागीदार इन्वेस्ट इंडिया तथा उद्योग भागीदार- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) है। शिखर सम्मेलन भारत की जी20 अध्यक्षता के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन जी20 देशों के निवेशकों के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय क्षेत्रों के साथ-साथ भारतीय पर्यटन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा।

# उप-मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में घटनास्थल का दौरा किया

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नये ओपीडी भवन के कैफेटेरिया में आग लगने की घटना के उपरांत घटनास्थल का दौरा कर महाविद्यालय प्रशासन से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। आरंभिक सूचना के अनुसार आईजीएमसी के नये ओपीडी भवन के सबसे ऊपरी मंजिल में संचालित कैफेटेरिया में रसोइ्र गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लगने की यह घटना पेश आयी है। उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त होते ही अस्पताल प्रशासन ने तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित किया और इससे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

उन्होंने समय रहते आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के प्रयासों की सराहना भी की।

इस अवसर पर विधायक भवानी सिंह पठानिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान, आईजीएमसी की प्रधानाचार्य डॉ. सीता ठाकुर सहित चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

# प्रदेश में 01 से 15 मई तक चलेगा जल जागरूकता अभियानः उप-मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 01 मई से 15 मई, 2023 तक जल जागरूकता अभियान चलाया जायेगा, जिसके माध्यम से पंचायत स्तर तक लोगों को जल गुणवत्ता एवं इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता समितियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों तथा विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से जल गुणवत्ता एवं जल संरक्षण के प्रति आम जनता को जागरूक करना है। अभियान के दौरान प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग मानसून से पहले गर्मी के मौसम में जल संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जनता में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के दृष्टिगत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को संवेदनशील बनाएगा और राज्य में जल गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अभियान के दौरान लैब टैस्ट के माध्यम से सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली के 13,670 के नमूनों की जांच की जाएगी तथा डिलीवरी प्वाइंट के अंतर्गत 9037 गांवों में भी प्रत्येक गांव के 2 घरों से पानी के नमूनों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया की फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से 12,975 स्कूलों एवं 13,327 आंगनबाड़ी केंद्रों से भी पानी के नमूनों की जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस अभियान में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत 27,340 सार्वजनिक जल वितरण क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा जल जागरूकता पर आधारित जल स्रोत यात्रा, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्कूल प्रतियोगिताएं, सामूहिक चर्चा, स्वच्छता जागरूकता इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं।

# राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क सेवाएं होंगी सुदृढ़

**शिमला/शैल।** हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में राज्य के कई अनछुए गंतव्य स्थलों की ओर देश और विदेश के पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सुलभ और सुविधापूर्ण परिवहन के साधन उपलब्ध करवाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

हिमाचल प्रदेश रेल, सड़क और हवाई संपर्क के माध्यम से देश के अलग-अलग स्थानों से जुड़ा है। हवाई सेवा और पर्यटन एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश में आने वाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक अच्छी कनेक्टिविटी चाहते हैं और हवाई सेवाएं इसमें मुख्य भूमिका निभा सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हवाई परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं। रामपुर, बद्दी, कांगनीधार (मंडी) और सासे (हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान), मनाली में हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ सुविधा-संपन्न पर्यटक कम समय में हिमाचल के अनछुए पर्यटक स्थलों में पहुंच पाएंगे।

शिमला शहर में संजौली और सोलन के बद्दी हेलीपोर्ट से हेली-टैक्सी सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, किन्नौर और ऊना जिलों को हवाई सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए यहां हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इन हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास के लिए 30 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार हेलीपोर्ट के निर्माण के साथ-साथ हवाई अड्डों के विस्तार व निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के अलावा मण्डी में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भी प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। मंडी हवाई अड्डे का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (एसआईए) सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इसके उपरांत भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में तेजी लायी जा रही है। कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई मौजूदा 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,010 मीटर करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बड़े हवाई जहाजों की लैंडिंग में सुविधा होगी और लोगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी।

राज्य सरकार वैश्विक पर्यटन स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य के प्रमुख शहरों के लिए हवाई संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में यातायात जैसी समस्या से निजात दिलाएगा।

# आईजीएमसी के न्यू ओपीडी भवन में आग की घटना की जांच के आदेशःस्वास्थ्य मंत्री

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के न्यू ओ. पी.डी. ब्लॉक की कैंटीन में आग लगने की घटना का विस्तृत ब्यौरा लिया। इस घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है तथा कैंटीन के साथ लगते चिकित्सकों के कुछ चैंबर्ज को नुकसान हुआ है।

वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के अपने दो दिवसीय प्रवास पर हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से दूरभाष पर इस घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही के संबंध में अस्पताल प्रबंधन को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं।

# एचपी शिवा परियोजना के तहत 15 हजार बागवान परिवार होंगे लाभान्वित

**शिमला/शैल।** बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने महक योजना और एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों व किसानों की हितैषी है तथा उनके कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। परियोजना के पहले चरण में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फलों के लगभग 65 लाख उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण प्रस्तावित है। दूसरे चरण में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा तथा प्रदेश में परियोजना के तहत कुल 15 हजार बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को पौधशालाओं के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त जगत सिंह नेगी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लघु प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि महक योजना के तहत विभिन्न जिलों के 1000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने महक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना से संबंधित कार्य योजना को 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान विधायक शाहपुर, केवल सिंह पठानिया ने बागवानी मंत्री से कांगड़ा के धारकंडी क्षेत्र में बागवानी विविधता को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजने का आग्रह किया ताकि फल व सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इस अवसर पर, एचपी शिवा परियोजना के परियोजना निदेशक देवेंद्र ठाकुर तथा बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

# प्रभावकारी नीति से राजस्व अर्जन में 40 प्रतिशत की वृद्धि

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। इसके लिए वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजस्व अर्जन के साधनों को बढ़ाया जा रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश की आबकारी नीति को व्यावहारिक बनाया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 में आबकारी नीति से अपेक्षित 2357 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राज्य कोष में 2800 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। पिछले लगभग 15 वर्षों में राज्य सरकार की आबकारी नीति के तहत राजस्व अर्जित 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज नहीं की गयी थी जबकि वर्ष 2011-12 में राजस्व में 25.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी।

पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछली सरकार के शासन के दौरान शराब की दुकानों का नवीनीकरण के माध्यम से 1296 करोड़ रुपये अर्जित किए गए, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान नीलामी एवं निविदा से 1815 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया जो 520 करोड़ रुपये अधिक है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा शराब के दुकानों के नवीनीकरण के निर्णय से सरकारी कोष को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने शराब की दुकानों की नीलामी करने और समग्र राजस्व बढ़ाने के लिए आबकारी नीति में नवीन उपाय किए।

सरकार के नीतिगत निर्णय से दुकानों की नीलामी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई है और इसमें पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया है। वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में सरकारी राजस्व में वृद्धि करने, शराब की कीमतों में कमी और पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। देसी शराब का निर्धारित कोटा 7.5 प्रतिशत और भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) का निर्धारित कोटा 5 प्रतिशत बढ़ाया गया है। थोक दुकानों के लिए वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क को 20 लाख बढ़ाकर 35 लाख रुपये, वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा उठाने के बाद, अतिरिक्त कोटा उठाने के लिए लाइसेंसधारियों को निर्धारित लाइसेंस शुल्क 80 प्रतिशत के साथ 10 प्रतिशत तक कोटा उठाने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक को निर्धारित लाइसेंस शुल्क के 90 प्रतिशत की दर से 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कोटा उठाने की अनुमति दी गयी है। राज्य सरकार के इन सभी उपायों से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब उत्पादन के सांचालन, थोक विक्रेताओं को इसकी आपूर्ति और खुदरा विक्रेताओं को बाद में बिक्री की निगरानी के लिए सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य की वाइनरी में आयातित शराब की बॉटलिंग की अनुमति दी गयी है।

वर्तमान आबकारी नीति में एल-3, एल-4 और एल-5 लाइसेंसधारकों को तीन सितारा होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान की गयी है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राज्य में राजस्व के स्रोत भी बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये 'दूध उपकर' लगाया है जिससे 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व अर्जित होगा। सरकार द्वारा इस फंड का उपयोग किसानों की बेहतरी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

# झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस से जनता माँग रही 10 गारंटियों का हिसाबःअनुराग सिंह ठाकुर

**शिमला/शैल।** केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शिमला में नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष जनसभाएँ व रोड शो कर शिमला के चहुँओर विकास के लिए निगम में फिर भाजपा को जिताने का अनुरोध किया। अनुराग ठाकुर ने वार्ड संख्या – 6 टूटू, वार्ड संख्या – 7 मज्याठ, वार्ड संख्या – 5 समरहिल में जनसभा व वार्ड संख्या – 33 खलिनी, वार्ड संख्या 13 कृष्णा नगर, सीटीओ लोअर बाज़ार में चुनाव प्रचार कर प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया।

शिमला में भाजपा द्वारा किये गए विकास कार्यों को दोहराते हुये ठाकुर ने कहा,' शिमला नगर निगम चुनाव में भाजपा के सभी उम्मीदवार पूरे जोश के साथ मज़बूती से चुनाव लड़ रहे हैं। शिमला की जनता ने इन निगम चुनावों में फिर से भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। हम अपने विकास कार्यों व कांग्रेस की नाकामियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। शिमला में आज ये जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है यह भाजपा की देन है। पहले शिमला की सड़कें तंग थीं, पानी की समस्या, गन्दगी की दिक्कत थी और विकास न के बराबर था। प्रधानमन्त्री ने कोई 5 – 10 करोड़ नहीं बल्कि 6500 करोड़ शिमला और धर्मशाला के स्मार्ट सिटी के लिए दिया है। आज सड़कों का चौड़ीकरण जो आप देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के आशीर्वाद से किया है। कारों की पार्किंग की सुविधा, अलग अलग वार्डों में पार्किंग की सुविधा जो आप देखते हैं और 700 और कारों की पार्किंग की सुविधा जो बनने जा रही है, ये सब भी भाजपा की देन है. शिमला में पिछले पांच वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। पानी की समस्या से मुक्ति हेतु 1800 करोड़ रूपये के प्रावधान किये गए। भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेशन बनने के बाद विकास के अनेकों और काम किये जायेंगे।

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा 'हमने शिमला सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या का निवारण किया। नयी तारों का बिछना हो या ट्रांसफार्मर्स हो सब लगवाने का काम किया है। हमने स्वास्थय की सुविधा दी और कांग्रेस ने 5 महीने में हीं उसे बंद करने का काम किया है। अगर आप दे नहीं सकते तो कम से कम छीनने का काम ना करें। सत्ता में भाव होना चाहिए। विकास आपके सोच में होना चाहिऐ सिर्फ पांच महीने में ही कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल हैं। शिमला कारपोरेशन के चुनाव में इनकी गारंटियाँ काम नहीं आयीं। झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस से जनता इनकी 10 गारंटियों का हिसाब माँग रही है।

ठाकुर ने आगे कहा, 'सरकार में आने से पहले कांग्रेसी बोलते थे हम कर्ज़ा नहीं लेंगे बल्कि कर्ज़ा चुकाएंगे। रोज़ का 40 करोड़ कर्ज़ा यानी लगभग 6 हज़ार करोड़ का कर्ज़ा ये सरकार पिछले पांच महीनों में ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश को कर्ज़े में डुबाने का काम कर रही है। इनके विधायक कहीं जन्मदिन मना रहे हैं और मंत्री विदेशों में घूम रहे हैं। कोई जनता से मिलने को तैयार नहीं है। इस सरकार के बनते हीं लूट की खुली छूट मिल गयी है। जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है और इन चुनावों में कांग्रेस पर वोट का चोट कर उनके झूठे वादों के लिए सबक़ सिखाने जा रही है।

शिमला कारपोरेशन चुनावों में भाजपा की जीत पर पूरा भरोसा जताते हुए ठाकुर ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी शिमला कारपोरेशन के चुनाव में अपने विकास कार्यों को लेकर जा रही है. आज आप कहीं भी किसी वार्ड में चले जाइये लोग बोलते मिल जायेंगे की ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए दिल से तैयार हैं।

# व्यवस्था परिवर्तन एक जुमला हैःजयराम

**शिमला/शैल** भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा हमने शिमला नगर निगम के सभी वार्डों में जन संपर्क किया है और इस दौरान जनता में भाजपा के लिए अद्भित जोश देखने को मिला, यह हमारी अपेक्षा से ऊपर है। जनता की बात सुनी जाए तो यह सामने आता है की जनता का मूड भाजपा के पक्ष में है।

अगर हम नगर निगम में 25 साल कांग्रेस के और 5 साल भाजपा के तुलना करे तो भाजपा के 5 साल कांग्रेस पर भारी पड़ रहे है। शिमला शहर के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है उन्होंने शिमला को स्मार्ट सिटी की बड़ी सौगात दी है। शिमला को रोप वे, एलिवेटर, रोड, पानी, बिजली और स्वच्छता मिली है जो की भाजपा के अथक प्रयासों का फल है।

नगर निगम चुनावों में कांग्रेस के प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री स्व.वीरभद्र सिंह का फोटो सभी जगह से गायब है साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का फोटो भी गायब है।

भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की जनता को 125 यूनिट फ्री दिए, महिलाओं के बस किराया को आधा किया। यह हमारी गारंटी नहीं थी पर फिर भी हमने काम किया। उन्होंने कहा की व्यवस्था परिवर्तन एक जुमला है यह जनता को पता चल गया है।

# भाजपा नेता विपिन परमार का बड़ा ब्यान नगर निगम के बाद प्रदेश में बनेगी भाजपा की सरकार

**शिमला/शैल।** नगर निगम शिमला के चुनावो के बीच बीजेपी विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनावों को कांग्रेस पार्टी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस गारंटियों को पूरा तो कर नहीं पा रही है। कांग्रेस के दिग्गज कह रहे हैं कि कांग्रेस में उनका गला घुट रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी नगर निगम में भी फिर से बहुमत से काबिज होगी और प्रदेश में भी उनकी सत्ता लौटेगी। हालांकि कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी से संपर्क में होने का सवाल वो टाल गए उन्होंने कहा कि वह मौके आने पर बताएंगे की कितने विधायक उनके संपर्क में हैं।

विपिन परमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि शिमला में ज्यादा समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा लेकिन यहां हिल्स क्वीन में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी पीएम और जयराम ठाकुर की देन है। कांग्रेस शिमला के लिए पानी और अन्य योजनाओं की बात कर रही हैं यह सब बीजेपी की देन है। पर्वतमाला और पानी की योजना बीजेपी लेकर आयी हैं।

पांच लाख रोजगार देने की बात करने वालो ने व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने करोना काल में सेवाएं देने वालो को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों में बिना इंटरव्यू के अध्यापकों के पद भरने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री इसको नकार देते हैं। सीएम और मंत्रिमंडल के बीच कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस ने राजधर्म की धज्जियां उड़ाई है।

# आईजीएमसी में आग लगने पर हो जांचःजयराम

**शिमला/शैल।** भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने आईजीएमसी का दौरा किया, आईजीएमसी में आग लगने के कारण नए ओपीडी में भारी नुकसान हुआ। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि आईजीएमसी में आग लगने के कारण अस्पताल की संस्था को भारी नुकसान हुआ है, हमें इस प्रकरण से सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे न हो इसके बारे में विचार करना चाहिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यह आग लगी इसके परिणाम काफी गंभीर भी हो सकते थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन को इस प्रकरण पर गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए एक जांच समिति भी तय करनी चाहिए।

# स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना भाजपा का संकल्प : जयराम

**शिमला/शैल।** पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शिमला नगर निगम चुनावो में बड़ा बहुमत प्राप्त होने वाला है। उन्होनें कहा कि कांग्रेस की गारंटियां खोखली साबित हुई है और चार माह के समय में ही जनता का कांग्रेस सरकार से मोह भंग हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले शिमला में पानी की काफी किल्लत रहती थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया है। भाजपा ने शिमला शहर को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने के लिए 1813 करोड़ रू की पेयजल योजना स्वीकृत करवाई। स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना भाजपा का संकल्प है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और नगर निगम शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर वामपंथी दल के थे तो पूरे शिमला शहर में भयंकर पीलिया फैला था और पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ था।

उन्होनें कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिमलावासियों को 40 हजार लीटर स्वच्छ जल मुफ्त उपलब्ध करवाने की घोषणा की है जिसे भाजपा की नगर निगम बनने पर लागू किया जाएगा। साथ ही पानी के मीटरों के लिए एन.ओ.सी. की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर नगर निगम शिमला पर भाजपा अपना विजयी परचम लहराएगी।

# भाजपा नगर निगम में एक बार फिर लहराएगी परचमः बिंदल

**शिमला/शैल।** भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा.राजीव बिंदल ने खलीनी और जाखू वार्ड में धुआंधार प्रचार किया। डा. बिंदल ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है और इस जोश से हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा नगर निगम शिमला में पूर्ण बहुमत हासिल जा रही है।

उन्होंने कहा कि पूरे शिमला में हमारी नगर निगम ने कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है और यही कारण है कि जनता भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जनता को पता है कि अगर सच में कोई विकास कर सकता है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी है, हमारी पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। हम अपने दृष्टि पत्र के सभी वायदों को पूरा करेंगे शिमला में चाहे सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो या बिजली की व्यवस्था हो उसको भारतीय जनता पार्टी ने और सुदृढ़ बनाया है ।

कांग्रेस और भाजपा में जनता फर्क समझ गयी है और इस बार 2 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। भाजपा नगर निगम में एक बार और परचम लहराने वाली है।

# सुरेश कश्यप ने कांग्रेस को दी नसियत झूठ की राजनीति लंबे समय के लिए नहीं चलती

**शिमला/शैल।** भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन नगर निगम चुनावों में जनता को गुमराह करने में असफल रहेगी, जिस प्रकार से झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में आयी थी और जितने भी वायदे उन्होंने जनता से किए थे उसमें से अभी तक एक भी कांग्रेस पूरा नहीं कर पायी है परिणामस्वरूप जनता ने मन बना लिया है कि शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है और इन चुनावों में भी हमने जो वादे जनता से किए हैं उन सभी को हम पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस एक विभाजित राजनीतिक दल है और उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप इन नगर निगम चुनावों में देखने को मिला है, आपसी फूट के कारण कांग्रेस पार्टी को अधिकतम वार्डों में हार का सामना करना पड़ेगा। झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती है और इन चुनावों में यह स्पष्ट हो जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.com

# नगर निगम में किसके वायदों पर क्यों और कैसे भरोसा करेगी शिमला की जनता

**शिमला/शैल।** नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। आप 21 वार्डो में और सी.पी.एम. चार वार्डो में चुनाव लड़ रहा है यदि यह दल इस चुनाव में खाता खोल पाये तो स्थिति त्रिशंकु सदन की होने की हो जायेगी। क्योंकि जब सी.पी.एम. के पास महापौर और उपमहापौर के दोनों पद सीधे मुकाबले में थे तब भी उनके पार्षदों की संख्या बहुत कम थी। अब भी अपने संसाधनों के अनुसार वह वही चुनाव लड़ रहे हैं जहां उनकी स्थिति मजबूत है। शिमला में सी.पी.एम. के पास वोट हैं जो निर्णायक भूमिका अदा करेगा। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने उस समय आधार दे दिया जब उसके एक प्रत्याशी को मुख्यमंत्री से मिलकर कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव से हटने की खबरें फोटो के साथ छप गयी। लेकिन बाद में यह प्रकरण सिरे नहीं चढ़ा और आप को यह आरोप लगाने तथा शिकायत करने का आधार मिल गया कि सरकार उनके प्रत्याशियों को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। इसलिये माना जा रहा है कि यह छोटे दल बड़ों का गणित निश्चित रूप से बिगाड़ेंगे।

## कहां खड़ी है कांग्रेस

इस परिदृश्य में कांग्रेस का आकलन करते हुए जो स्वभाविक प्रश्न उठते हैं उन पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जनता को दस गारंटियां दी थी। यह गारंटियां देने के बाद कांग्रेस को 40 सीटें तो मिली गयी। लेकिन प्रदेश स्तर पर कांग्रेस को केवल 0.6% वोट ही भाजपा से ज्यादा मिल पाये। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में काफी समय लग गया। फिर मंत्रियों की शपथ से पहले मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिलानी पड़ी। मुख्य संसदीय सचिवों का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। अदालत इसमें नोटिस जारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2017 में ही असम के मामले में ऐसी नियुक्तियों को गैरकानूनी कह चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल की एस.एल.पी. का भी संज्ञान लिया हुआ है। इसलिये यह माना जा रहा है कि हिमाचल की यह नियुक्तियां अदालत में ठहर नहीं पायेंगी। संभवत: इसी संभावित वस्तु स्थिति को लेकर जयराम और विपिन परमार सरकार के गिरने की ब्यानबाजी कर रहे हैं। कानून के जानकार जानते हैं कि यह होना तय है।

इससे हटकर दूसरा पक्ष सरकार के प्रशासन का है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कोई ऐसा प्रशासनिक फेरबदल नहीं हुआ जिससे कांग्रेस के

कार्यकर्ताओं और आम जनता को यह सीधा सन्देश जा पाता कि सरकार बदल गयी है। सरकार बदलने पर प्रदेश भर में पार्टी के पांच-सात हजार कार्यकर्ता शिमला से लेकर चुनाव क्षेत्रों तक विभिन्न कमेटियों में समायोजित हो जाते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। जिन चार-पांच लोगों को पदों से नवाजा गया है उनसे भी यही सन्देश गया है कि कालान्तर में यह लोग अपने-अपने क्षेत्रों में चयनित विधायकों/मंत्रियों के लिये समानान्तर सत्ता केंद्र हो जायेंगे। सरकार ने पदभार संभालते प्रदेश की वित्तीय स्थिति के श्रीलंका जैसे होने की बात की थी। परन्तु इस स्थिति पर न तो सदन में श्वेत पत्र ला पायी न ही अपने खर्चों पर कोई नियंत्रण किया। उल्टे डीजल, सरसों का तेल, बिजली और पानी के रेट बढ़ा दिये। जो 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया था उस पर अब यह शर्त लगा दी कि पहले दो हजार मेगावाट पैदा करेंगे उसके बाद तीन सौ यूनिट मुफ्त देने का वादा पूरा करेंगे।

युवाओं को जो रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा किया था उसमें खाली पदों का आंकड़ा तो जारी हो गया लेकिन शिक्षा विभाग में प्रस्तावित नयी नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री और मंत्री में ही तालमेल न होने का कड़वा सच बाहर आ गया है। नगर निगम चुनाव जीतने के लिये आचार संहिता को अंगूठा दिखाते हुये शिमला के भवन मालिकों को एटिक और बेसमैन्ट के नियमों में संशोधन करके राहत देने और फीस के रूप में अपना राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया गया है। शिमला में भवन निर्माण में 2016 में एन.जी.टी. का फैसला आने से जटिलता बढ़ा है। इस फैसले को सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है लेकिन इस पर कोई स्टे नहीं है। ऐसे में कानून की समझ रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि फैसले को निरस्त हुए बिना सरकार केवल आश्वासन दे सकती है और कुछ नही कर सकती। वाटर सैस लगाने के मामले को केंद्र सरकार ने असंवैधानिक और गैरकानूनी कह रखा है। उच्च न्यायालय में यह मामला भी पहुंच चुका है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संसाधन जुटाने के लिये कर्ज और कर का ही सहारा लेना पड़ेगा। पूर्व सरकार भी ऐसा ही करती रही है।

इस समय सुक्खू सरकार पर प्रतिदिन चालीस करोड़ का कर्ज लेने का आरोप लग चुका है। भाजपा कांग्रेस की दस गारंटीयों पर दस सवाल दाग चुकी है। इन सवालों को घर-घर तक पहुंचा दिया गया है। जबकि कांग्रेस अपने घोषणापत्र को भाजपा की तर्ज पर छाप कर व्यापक प्रसार नहीं कर पायी है। इस परिदृश्य में कांग्रेस के पास सरकार होने के अतिरिक्त और कुछ पक्ष में नही है। जयराम ने कांग्रेस के पोस्टरों में स्व. वीरभद्र सिंह, खड़गे और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के फोटो गायब होने पर चुटकी ली है।

# क्या भाजपा के वायदे कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं

- चालीस हजार लीटर पानी प्रतिमाह मुफ्त
- गारवेज बिल आधा
- जहां ढारा वहीं मकान
- कांग्रेस के वायदों पर भरोसा तो भाजपा पर क्यों के मुकाम पर पहुंची स्थिति
- कांग्रेस की दस गारंटियां ही बन गयी भाजपा के दस सवाल
- चालीस करोड प्रतिदिन कर्ज लेने के खुलासे पर कांग्रेस चुप क्यों?

**शिमला/शैल।** विधानसभा चुनाव की हार का आकलन भले ही भाजपा ने सार्वजनिक न किया हो लेकिन नगर निगम चुनावों में अपनाई रणनीति से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इन चुनावों के लिये बहुत गंभीर है। नगर निगम शिमला के चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भाजपा हाईकमान भी इन चुनावों पर नजर बनाये हुये है। यह इससे प्रमाणित हो जाता है कि भाजपा ने इन चुनावों के बीच अपने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को बदल दिया तथा प्रभारी भी उत्तर प्रदेश से लगा दिया। इस बदलाव से भाजपा का पूरा कॉडर फिर से सक्रिय हो उठा है। यह कहा जा रहा है कि सुक्खू सरकार के फैसलों से कि भाजपा को बल मिल रहा है। सुक्खू सरकार के पहले ही फैसले से भाजपा को मुद्दा मिल गया। जिसे उसने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रदेश के हर कोने से लेकर उच्च न्यायालय तक भी पहुंचा दिया। विधानसभा में भी सरकार को यह कहना पड़ा कि जहां आवश्यक होगा वहां संस्थान खोल दिये जायेंगे। यही नहीं अपने कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे अधिकारी को मुख्य सूचना आयुक्त और वित्त सचिव को मुख्य सचिव बनवा लिया। अब मुख्य संसदीय

सचिवों की नियुक्ति का मामला उच्च न्यायालय में पहुंच जाने के कारण सरकार गिरने की भविष्यवाणियां करने का अवसर मिल गया है। फिर जब सरकार अपने वायदे के बावजूद प्रदेश की आर्थिकी पर सदन में श्वेत पत्र नहीं ला पायी तो जयराम सरकार को स्वत: ही वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों से क्लीन चिट मिल गयी है। बल्कि सरकार पर प्रतिदिन चालीस करोड़ का कर्ज लेने का आंकड़ा जनता तक पहुंचा कर उल्टे सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार एक सच को सामने रखकर विश्लेषकों को यह मानने पर बाध्य कर दिया है कि रणनीतिक तौर पर भाजपा सरकार पर भारी पड़ रही है।

## क्या है भाजपा के वायदे

इसी के साथ यदि भाजपा के चुनावी वायदों पर नजर डालें तो सबसे पहले शिमला के नागरिकों को प्रतिमाह चालीस हजार लीटर पानी मुफ्त देने का वायदा किया गया है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं इस पर दी हैं। मुख्यमंत्री ने इसे झूठ करार दिया है क्योंकि कांग्रेस ने शहरी निकाय क्षेत्रों में ही पानी की दरें बढ़ायी हैं। ऐसे में यदि भाजपा के वायदे झूठे हैं तो कांग्रेस के सच्चे कैसे हो सकते हैं। गारवेज उठाने के बिल आधा करने की बात की है। शहर में करीब एक दर्जन झुग्गी झोपड़ी बस्तीयां हैं। इनके लोगों को जहां ढारा वहीं मकान का वायदा अपने में बहुत प्रभावी हो जाता है। भाजपा के यह वायदे निगम क्षेत्र के हर व्यक्ति को सीधे प्रभावित करते हैं और उसने यह वायदे प्रिन्ट में हर घर तक पहुंचा दिये हैं। इस तरह वायदों के बिन्दु पर भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। यह स्वभाविक है कि यदि जनता ने कांग्रेस के वायदों पर विश्वास किया है तो उसी तरह से भाजपा के वायदों पर भी भरोसा किया जायेगा। इस तरह यह चुनाव इस मुकाम तक पहुंच गया है जहां कांग्रेस के लिये स्थिति गंभीर हो गयी है।